महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जनवरी से अक्टूबर 2018

Powered by :

gradeup

करंट अफेयर्स
महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं
जनवरी से अक्टूबर 2018

प्रिय पाठक,

यह पीडीऍफ़ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की एक पूरी डॉकेट है जो पिछले 10 महीनों में हुई थी **(1 जनवरी 2018 - 31 अक्टूबर 2018)**। यह फाइल, Banking, SSC, UPSC, PCS, राज्य और सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है।

योजनाएं

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं

अक्टूबर

1. स्पार्क योजना

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अक्टूबर 2018 में 'एस.पी.ए.आर.सी.' योजना शुरू की।
- इस योजना का उद्देश्य सामाजिक और स्पष्ट विज्ञान में भारत के विशिष्ट शोध को बढ़ावा देना है।

यहां 'स्पार्क' का अर्थ है - 'अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना'।

SPARC' stands for - **'Scheme for promotion of Academic and Research Collaboration'.**

स्पार्क योजना का उद्देश्य -

- स्पार्क योजना का लक्ष्य भारतीय संस्थानों और दुनिया के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाकर भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है।

योजना के मुख्य बिंदु:

- स्पार्क योजना में दो वर्ष में कुल 418 करोड़ रुपये के कुल व्यय के लिए लगभग 600 प्रस्तावों का समर्थन करने की योजना की परिकल्पना है।

बजट व्यय -

- मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) मंत्रालय ने भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोगी अनुसंधान पर 2018-20 से 418 करोड़ रुपये का बजट घोषित किया।

विदेशी देशों के साथ सहयोग:

- स्पार्क योजना भारतीय संस्थानों के बीच 28 चयनित देशों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन की सुविधा प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय समन्वय संस्थान -

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर एस.पी.ए.आर.सी. कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान है।

योग्यता -

- भारतीय रैंकिंग (एन.आई.आर.एफ.) में कुल प्रमुख 100 या श्रेणीवार प्रमुख 100 में रैंक किए गए सभी भारतीय संस्थान आवेदन करने के लिए योग्य हैं।
- उपरोक्त श्रेणी में आने वाले ऐसे निजी संस्थान, और यू.जी.सी. अधिनियम की धारा 12(8) के तहत भी मान्यता प्राप्त हैं।
- साझेदार संस्था Q5 विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग के शीर्ष 500 में या विषय के अनुसार Q5 विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग के शीर्ष 200 में होगी।

2. इंप्रेस योजना

- सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में नीति अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में 'इंप्रेस' योजना की शुरूआत की।

'इंप्रेस' का अर्थ है - सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान।

'IMPRESS' stands for - Impactful Policy Research in Social Sciences.

मुख्य बिंदु -

- यह योजना देश के किसी भी संस्थान में सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगी इसमें सभी विश्वविद्यालय (केंद्रीय और राज्य) शामिल हैं।
- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि समाज की प्रगति हेतु सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान आवश्यक है और इंप्रेस योजना के तहत किए गए शोध का उपयोग समाज के सामने आने वाली समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए किया जाएगा।
- **बजट व्यय -** योजना मार्च 2021 तक 414 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ लागू की जाएगी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी-** यह योजना भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद (आई.सी.एस.एस.आर.) द्वारा लागू की जाएगी।
- इम्प्रेस योजना प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति पर प्रत्यक्ष प्रभाव के उद्देश्य से शोध में नए मार्ग खुलेंगे- बी.बी. कुमार (आई.सी.एस.एस.आर. अध्यक्ष)
- इम्प्रेस योजना के तहत, उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 1,500 अनुसंधान परियोजनाओं को दो वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा।

इंप्रेस योजना के उद्देश्य - इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार है

- शासन एवं समाज पर अधिकतम प्रभाव के साथ सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान करना और निधि एकत्र करना।
- ऑनलाइन मोड पर एक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से परियोजनाओं का चयन सुनिश्चित करना।
- देश में किसी भी संस्थान में सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं के लिए सभी विश्वविद्यालयों (केंद्रीय और राज्य), यू.जी.सी. द्वारा प्रदान की गई 12(B) स्थिति वाले निजी संस्थान को अवसर प्रदान करना

इम्प्रेस योजना के तहत पहचाने गए डोमेन इस प्रकार हैं:

- राज्य और लोकतंत्र
- शहरी परिवर्तन
- मीडिया, संस्कृति और समाज
- रोजगार कौशल और ग्रामीण परिवर्तन
- शासन, नवाचार और सार्वजनिक नीति
- विकास, दीर्घ व्यापार और आर्थिक नीति
- कृषि और ग्रामीण विकास
- स्वास्थ्य और पर्यावरण
- विज्ञान और शिक्षा

- सोशल मीडिया एवं प्रौद्योगिकी
- राजनीति, कानून और अर्थशास्त्र

3. **सरकार ने युवा सड़क सुरक्षा शिक्षार्थियों लाइसेंस कार्यक्रम शुरू किया**

• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नई दिल्ली में युवा सड़क सुरक्षा शिक्षार्थियों लाइसेंस कार्यक्रम शुरू किया है।

• यह डायजियो इंडिया और रोड ट्रैफिक एजुकेशन संस्थान (आईआरटीई) के सहयोग से सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) पहल है।

• यह कार्यक्रम 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।

4. **दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अर्बन लीडरशिप प्रोग्राम:**
   - दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अर्बन लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया है जो देश भर के युवा नेताओं को आकर्षित करने के लिए है ताकि इसके साथ शहर की गंभीर चुनौतियों को संबोधित करने का प्रयास किया जा सके| इसकी घोषणा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया ने की|
   - इसके लिए युवा नेता को पारिश्रमिक भुगतान के रूप में प्रति माह 1.25 लाख रुपये और सहायक नेता को प्रति माह 75,000 रु दिये जाएंगे|
5. **केंद्र सरकार ने सदस्यता के लिए सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना की नई श्रृंखला शुरू की हैं|**
   - इस योजना के तहत, अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक हर महीने सार्वभौमिक स्वर्ण बांड जारी किए जाएंगे।
   - यह बॉन्ड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज (NSE और BSE) के माध्यम से बेचे जाएंगे|
6. **सार्वभौमिक स्वर्ण बांड (SGB) योजना**
   - इसका उद्देश्य भौतिक सोने की खरीद का विकल्प प्रदान करना है|
   - इसके तहत, बांड सोने के एक ग्राम और उसके गुणकों की इकाइयों में अंकित किए जाएंगे|
   - इन बांडों की बिक्री केवल व्यक्ति विशेष, एचयूएफ (संयुक्त हिंदू परिवार), ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और चैरिटेबल संस्थान समेत निवासी भारतीय निकायों तक ही सीमित रहेगी।
   - व्यक्ति विशेष और एचयूएफ के लिए न्यूनतम निवेश की अनुमति 1 ग्राम और अधिकतम 4 किग्रा है|
   - ट्रस्ट और समान इकाइयों के लिए, अधिकतम निवेश अनुमति प्रति वर्ष 20 किग्रा है|
   - आरबीआई ने एसजीबी बॉन्ड पर सालाना 2.50% की ब्याज दर अधिसूचित की है जो अर्ध वार्षिक आधार पर देय है।
7. डिजी यात्रा: सरकार ने हवाई अड्डे पर यात्रियों की बॉयोमीट्रिक आधारित डिजिटल प्रसंस्करण पर नीति जारी की है|
   - केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने डिजी यात्रा नामक हवाई अड्डों पर यात्रियों की बॉयोमीट्रिक आधारित डिजिटल प्रसंस्करण पर नीति जारी की है।
   - पहल का उद्देश्य पेपरलेस और परेशानी मुक्त हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है|
   - यह बेंगलुरु और हैदराबाद हवाई अड्डों पर फरवरी 2019 के अंत तक शुरू हो जाएगी|
   - इसके बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) कोलकाता, वाराणसी, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर अप्रैल 2019 तक इस पहल को शुरू करेगा।

मुख्य बिन्दु:

- डिजी यात्रा के तहत, आईडी का उपयोग करते हुए, पहली बार करते समय यात्रा प्रस्थान हवाई अड्डे पर केवल एक बार का सत्यापन होगा।
- सत्यापन के बाद, चेहरे की पहचान बायोमेट्रिक पर दर्ज हो जाएगी और डिजी यात्रा आईडी में स्टोर हो जाएगी|
- इस पहल के साथ, टिकिट बूकिंग, एयरपोर्ट एंट्री, और बोर्डिंग पास सेक्युर्टी चेक-इन डिजिटल रूप से किए जा सकते हैं|

- इस प्रक्रिया के लिए, यात्रियों को केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा और डिजी ट्रैवल आईडी दी जाएगी|

8. उद्यम अभिलाषाएल: सिडबी (SIDBI) ने राष्ट्रीय स्तरीय उद्यमिता जागरूकता अभियान लॉच किया है|

- लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने उद्योग अभिलषा एक राष्ट्रीय स्तर उद्यमिता जागरूकता अभियान शुरू किया है।
- इसे 28 राज्यों में नीति आयोग स्वीकृत 115 आकांक्षी जिलों में लॉन्च किया गया था।

उद्यम अभिलाषा का विषय

- महत्वाकांक्षी जिलों में ग्रामीण युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें उनका उद्यम स्थापित करने में सहायता करना।
- डिजिटल माध्यम से पूरे देश में प्रशिक्षण प्रदान करना,
- CSC-VLE के लिए व्यवसाय अवसरों का सृजन.
- महिलाओं की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वाकांक्षी जिलों में महिला उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित करना।
- प्रतिभागियों को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से बैंक योग्य बनने और क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने में सहायता करना।

9. ओडिशा सरकार ने 'निर्मन कुसुम' योजना शुरू की - ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अपनी तकनीकी शिक्षा के लिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'निर्मन कुसुम' कार्यक्रम शुरू किया|

मुख्य बिन्दु:

- निर्माण श्रमिकों के बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और पॉलिटेक्निक में अपनी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
- एक आईटीआई छात्र प्रति वर्ष 26,300 रुपये जबकि एक डिप्लोमा छात्र 26,300 रु की वित्तीय सहायता पाने के हकदार होंगे|.
- कार्यक्रम से कुल 1,878 छात्रों को लाभ मिलेगा|

10. उड़ीसा सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना लॉच की- उड़ीसा सरकार ने गरीब लोगों को कवर करने के लिए राज्य की अपनी खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की।

11. इस योजना के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों से वंचित 25 लाख गरीब लोगों को एक रुपये में प्रति माह 5 किलोग्राम चावल मिलेंगे|

12. गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना:

- असम सरकार राज्य के चाय बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना की पेशकश करने वाली पहली राज्य सरकार बन गयी है|

मुख्य बिन्दु:

- इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वे स्वयं और नवजात शिशु की देखभाल कर सकें।
- गर्भवती महिलाओं को मजदूरी का मुआवजा 4 किश्तों में दिया जाएगा - पहले तिमाही में 2,000 रुपये, दूसरे तिमाही में 4,000 रुपये, संस्थागत डिलीवरी के लिए 3,000 रुपये और बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए 3,000 रुपये दिए जाएंगे।

सितंबर

1. अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमाकृत व्यक्तियों के लिए अटल बिमित व्यक्ति कल्याण योजना नामित नई योजना को मंजूरी दी है।

मुख्य बिन्दु:

- यह योजना बेरोजगारी या नहीं नौकरी ढूँढने के मामले में सीधे उनके बैंक खाते में नकदी पहुंचाने में सहायता करती है|

- बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों के लिए सुपर स्पेशियलिटी उपचार का लाभ उठाने की अर्हता में छूट देकर अब इसे एक वर्ष के बीमा योग्य रोजगार तक घटा दिया गया है, जिसमें 156 दिनों का अंशदान होगा|
- ईएसआईसी ने बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर भुगतान किए जाने वाले अंत्येष्टि व्यय में वर्तमान 10 हजार रुपये से 15 हजार रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है|

2. स्वयंसिद्ध योजना - मानव तस्करी से निपटने के प्रयास में, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्वयंसिद्ध नामक योजना शुरू की है। एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में राज्यों के बीच तस्करी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं|

योजना का उद्देश्य-

- इस योजना का उद्देश्य युवा लड़कों और लड़कियों को अधिक जागरूक व सशक्त बनाना है ताकि वे तस्करी और बाल विवाह के मामलों में संवेदनशील कम हों।
- स्वयंसिद्ध का अर्थ आत्मनिर्भरता है और इसे पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा निष्पादित किया जाएगा|

3. सीमा बुनियादी ढांचा और प्रबंधन (BIM) योजना- सीमा बुनियादी ढांचा और प्रबंधन (BIM) योजना- केंद्र सरकार ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे और प्रबंधन (BIM) की सह योजना के तहत 60 परियोजनाओं के लिए 8,606 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
   - परियोजनाओं को पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश सहित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले 17 राज्यों में 111 सीमा जिलों में लागू किया जा रहा है।
   - इस योजना के अंतर्गत सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने, सीमा पर्यटन, स्वच्छता मिशन, खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, पेयजल की आपूर्ति, विरासत स्थलों की सुरक्षा, सामुदायिक केंद्रों, कनेक्टिविटी, जल निकासी, टिकाऊ जीवन को सक्षम बनाना शामिल है।

4. **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना:**
   - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची, झारखंड में आयुषमान भारत के तहत महत्वाकांक्षी प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) की शुरुआत की है|
   - इस योजना का उद्देश्य भारत भर में 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों अर्थात लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है।
   - इसे दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थकेयर योजना के रूप में बताया गया है जो लाभार्थी आबादी की सहायता करेगा जो 27-28 यूरोपीय देशों के बराबर है और लगभग कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका की आबादी के बराबर है।
   - यह योजना 25 सितंबर, 2018 अर्थात दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर परिचालित हो जाएगी।

प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)

- PMJAY सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूरे भारत में किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त कवरेज मुहैया कराएगी|
- इसमें 30 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के 444 जिलों में सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण (SECC) 2011 के आधार पर स्वीकृत लाभार्थी परिवारों को शामिल किया जाएगा।

5. तमिलनाडु सरकार ने विदेशी नीला कुरिनजी पौधों की सुरक्षा के लिए योजना की घोषणा की
   - तमिलनाडु सरकार ने विदेशी नीला कुरिनजी (स्ट्रोबिलैंथस कुंथियानस) पौधों की सुरक्षा के लिए योजना की घोषणा की है जो कि 12 साल में केवल एक बार उगता है।

- यह योजना शिकायतों के बाद आयी है कि इन दुर्लभ और पारिस्थितिकीय अद्वितीय फूलों को वाणिज्यिक आधार पर पैक किया जा रहा है और बेचा जा रहा है।

6. **नीला कुरिनजी पौधा**
   - नीलाकुरीनजी एक उष्णकटिबंधीय पौधों की प्रजाति है। यह पश्चिमी घाटों में शोला जंगलों के मूल आवासीय है।
   - यह पूर्वी घाटों में शेवरो हिल्स, अनालालाई पहाड़ियों और केरल में आगाली पहाड़ियों और कर्नाटक में सांडुरु पहाड़ियों में भी देखा जाता है।
7. **दिल्ली सरकार ने आवश्यक सरकारी सेवाओं के घर-घर वितरण के लिए भारत की पहली योजना शुरू की**
   - दिल्ली सरकार ने जाति एवं विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और पानी के नए कनेक्शन जैसी 40 आवश्यक सरकारी सेवाओं के घर-घर वितरण के लिए योजना शुरू की है।
   - यह देश में विभिन्न आवश्यक सरकारी सेवाओं के घर-घर वितरण की पहली योजना है।
   - यह आवश्यक सरकारी सेवाओं के वितरण में भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शी शासन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
8. **प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) -** प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई एकछत्रीय योजना 'प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)' को मंजूरी दी। इस योजना का लक्ष्य किसानों को उनके उत्पादन के लिए वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में घोषित लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है।
   - **लक्ष्य -** इस योजना का लक्ष्य किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है।
   - **उद्देश्य -** किसानों को सशक्त बनाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत करना।
   - **आवंटन-** मंत्रिमंडल ने अगले दो वित्तीय वर्षों में PM-AASHA को लागू करने के लिए **15,053 करोड़ रूपये** आवंटित किए हैं, जिनमें से 6,250 करोड़ रुपये इस वर्ष खर्च किए जाएंगे।

   PM-AASHA के घटक: PM-AASHA के तहत, राज्यों को तीन योजनाओं में से किसी एक को चुनने की अनुमति दी जाएगी -
   मूल्य समर्थन योजना (PSS),
   मूल्य कमी भुगतान योजना (PDPS)
   निजी खरीद एवं थोक व्यापारिक योजना संचालन (PPPS)।
9. **सरकार ने अटल पेंशन योजना को अनिश्चित अवधि तक बढ़ाया** - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को अनिश्चित काल तक विस्तारित करने का फैसला किया है, जो अगस्त, 2018 में समाप्त हो गई थी ताकि इस योजना में लोगों की भागीदारी को अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।

   अटल पेंशन योजना (APY) -
   - यह वर्ष 2015 में सरकार द्वारा शुरु की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो 1000 रुपये से 5,000 रुपये तक की एक निर्धारित पेंशन प्रदान करती है।
   - इसने सरकार द्वारा समर्थित पूर्व पेंशन योजना स्वावलंबन योजना का स्थान लिया था।

   योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं:
   - **ओवरड्राफ्ट सुविधा दोगुनी** - वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा 5,000 रुपये 10,000 रुपये तक दोगुनी हो गई है।
   - **आयु सीमा में वृद्धि -** आयु सीमा को पहले की 18 से 60 वर्षों से 18 से 65 वर्ष में संशोधित किया गया है।
   - **दुर्घटना बीमा कवर में वृद्धि -** दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है।
10. **सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) में संशोधन -** सरकार ने PMJDY योजना में लोगों की भागीदारी को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए योजना में संशोधन किया है।

प्रमुख बातें

- **ओवरड्राफ्ट की सुविधा दोगुनी** - वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा 5,000 रुपये से 10,000 रुपये होकर दोगुनी हो गई है।
- **आयु सीमा में वृद्धि** - इसके तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा को पहले की 18 से 60 वर्षों से 18 से 65 वर्ष करके संशोधित किया गया है।
- **दुर्घटना बीमा कवर में वृद्धि** - नए रुपे कार्डधारकों के लिए दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है।

11. **स्वदेश दर्शन योजना:** पर्यटन मंत्रालय ने केरल में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 80.37 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

नोट:

- यह योजना केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में विषय-आधारित पर्यटक क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली परियोजना 'पूर्वोत्तर सर्किट: इम्फाल और खोंगजोम' का उद्घाटन मणिपुर में किया गया।
- इस परियोजना में मणिपुर में दो क्षेत्र कांगला किला और खोंगजोम शामिल हैं।

अगस्त

1. **O-SMART' योजना-** यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।

   प्रमुख बातें -

   - (O-SMART) का अर्थ है - महासागरीय सेवाएं, प्रौद्योगिकी, पर्यवेक्षण, संसाधन प्रतिरूपण और विज्ञान (Ocean Services, Technology, Observations, Resources Modelling and Science)।
   - O-SMART योजना में वर्ष 2017-18 और वर्ष 2019-20 के दौरान महासागरीय विकास गतिविधियों और विज्ञान के कार्यान्वयन के लिए 16 उप-परियोजनाएं शामिल हैं।
   - सी.सी.ई.ए ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1623 करोड़ रुपये की कुल लागत पर योजना को मंजूरी दी।

2. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने AICTE में इनोवेशन सेल लॉन्च किया** - केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में AICTE परिसर में इनोवेशन सेल की स्थापना की है।

   उद्देश्य- इसका उद्देश्य देश भर में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (एच.ई.आई) में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित रुप से बढ़ावा देना है।

3. **सरकार ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 का तीसरा संस्करण लॉन्च किया** - मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एच.आर.डी) में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 (एस.आई.एच-2019) का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है।
   - स्मार्ट इंडिया हैकथॉन दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक नवाचार मॉडल है जिसका उद्देश्य छात्रों को अपने दैनिक जीवन में लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्याओं को हल करने के लिए मंच प्रदान करना है।
4. **प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना (PMFBY) -** सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में वरिष्ठ नौकरशाह आशीष कुमार भूटानी को नियुक्त किया है।

   प्रमुख बातें-

   - यह किसानों को शीघ्र बीमा सेवाएं या राहत सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016 में शुरू की गई किसान कल्याण योजना है।
   - इसका उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम के बोझ को कम करना और पूर्ण बीमाकृत राशि के लिए फसल बीमा दावे के प्रारंभिक निपटारे को सुनिश्चित करना है।

- इस योजना के तहत, किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एकसमान प्रीमियम भुगतान करना होगा।
- वार्षिक व्यवसायिक और बागवानी फसलों के मामले में, किसानों को केवल 5% का प्रीमियम देना पड़ता है।
- किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम शुल्क बहुत कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।
- इसके अलावा, सरकारी की सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, इसलिए किसानों को बिना किसी कमी के पूर्ण बीमा राशि मिलेगी।

5. **PMS-OBC योजना -** आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए) ने वर्ष 2020 तक भारत में अध्ययन करने के लिए **अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति** (PMS-OBC) की केंद्र प्रायोजित योजना की निरंतरता और संशोधन को मंजूरी दी है।

प्रमुख बातें-

- PMS-OBC वर्ष 1998-99 के बाद से सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की प्रमुख योजना है।
- यह पूरी तरह से केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य मैट्रिक या माध्यमिक स्तर के बाद अध्ययन के लिए ओ.बी.सी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।
- संशोधित PMS-OBC के तहत, अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है।
- अब, 30% धन छात्राओं के लिए निर्धारित किया जाएगा और 5% विकलांग छात्रों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

6. **सी.सी.ई.ए ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के विस्तार को मंजूरी दी** - यह योजना 25 दिसंबर, 2000 को लॉन्च की गई थी।

- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी योग्य गैर-संबद्ध आवासों के लिए हर मौसम में उपयुक्त एकल सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

7. **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) -** केंद्र सरकार, नाबार्ड और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एन.डब्ल्यू.डी.ए) ने दीर्घकालिक सिंचाई कोष (एल.टी.आई.एफ) के माध्यम से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत 99 प्राथमिक सिंचाई परियोजनाओं की केंद्रीय हिस्सेदारी के वित्त पोषण के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन (एम.ओ.ए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रमुख बातें:

- PMKSY को जुलाई, 2015 में देश के सभी कृषि क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने और 'प्रति बूंद अधिक फसल' उत्पादन के लिए अति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया गया था, जिससे अधिक वांछित ग्रामीण समृद्धि लाई जा सके।
- यह कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण विकास मंत्रालयों द्वारा लागू किया गया है।
- इसमें अप्रैल, 2020 तक पांच वर्ष से अधिक की कार्यान्वयन अवधि के साथ 50000 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

नोट:

- सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के तहत समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) की स्थापना के लिए **5,000 करोड़ रुपये** की धनराशि को मंजूरी दी है।

8. **सरकार ने IMPRINT योजना के तहत 122 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी:** केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी) ने IMPRINT -2 (प्रभावी अनुसंधान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी) योजना के तहत वित्त पोषण के लिए 112 करोड़ रुपये के 122 नए शोध परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

नोट:

- IMPRINT अपनी तरह की पहली एम.एच.आर.डी समर्थित योजना है जो देश में 10 तकनीकी पहचान वाले क्षेत्रों में प्रमुख विज्ञान और इंजीनियरिंग चुनौतियों के समाधान और मूल वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए है।

- इसे नवंबर, 2015 में नई इंजीनियरिंग शिक्षा नीति विकसित करने और इंजीनियरिंग चुनौतियों का अनुसरण करने के लिए सड़क मानचित्र निर्माण के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

9. **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना:** सरकार ने 5 करोड़ मुफ्त एल.पी.जी कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त किया।
   - केंद्र सरकार ने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत निर्धारित अवधि से लगभग आठ महीने पहले (अर्थात् 35 महीने के बजाय 27 महीने में) 5 करोड़ मुफ्त एल.पी.जी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है।
   - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने PMUY को आंतरिक वायु प्रदूषण को संबोधित करने वाली सरकार की निर्णायक योजना के रूप में मान्यता दी है, जो देश में वार्षिक रूप से लगभग 10 लाख मृत्यु का कारण बनता है।

   प्रमुख बातें:
   - केंद्र सरकार ने मई, 2016 में 'स्वच्छ भारत, बेहतर जीवन' की टैगलाइन के साथ PMUY लॉन्च की थी।
   - इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को खाना पकाने के स्वच्छ-ईंधन प्रदान करना है, जो भिन्न-भिन्न प्रकार के आंतरिक वायु प्रदूषण से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के प्रति अतिसंवेदनशील है और इन्हें जीवन मानकों में गुणात्मक लाभ प्रदान करते हैं।
   - PMUY पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है।
   - इसकी बड़ी सफलता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने **12,800 करोड़ रुपये** के बजटीय आवंटन के साथ लक्ष्य को 8 करोड़ तक संशोधित किया था।

   नोट: उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एल.पी.जी कनेक्शन (87 लाख) दिए गए हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल (67 लाख) और बिहार (61 लाख) हैं।

10. **मुख्यमंत्री युवा नेस्तम:** आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने वाली योजना, मुख्यमंत्री युवा नेस्तम को मंजूरी दी।
    - भत्ता पारदर्शी तरीके से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से चयनित लाभार्थी के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। यह भविष्य निधि का भुगतान करने वालों पर लागू नहीं होगा।

11. **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) -** नीति आयोग ने RUSA योजना के लिए 117 जिलों की महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में पहचान की।
    - राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) की केन्द्र प्रायोजित योजना के दूसरे चरण के दौरान, नीति आयोग द्वारा पहचाने जाने वाले 'महत्वाकांक्षी जिलों' और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य में संरक्षित और गैर-संरक्षित जिलों में नए मॉडल डिग्री कॉलेज (एम.डी.सी) खोलने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
    - **नोट: RUSA** वर्ष 2013 में लॉन्च की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) है, जिसका उद्देश्य योग्य राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है।

जुलाई

1. **सुकन्या समृद्धि योजना:** केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों के लिए न्यूनतम वार्षिक जमा राशि **1000 रुपये से कम करके 250 रुपये** कर दी है।
   - खाता खोलने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक जमा धनराशि भी घटाकर 250 रुपये कर दी गई है।
   - इस कदम का उद्देश्य अधिक लोगों को कन्या बचत योजना का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है।

   प्रमुख बातें:
   - **उद्देश्य -** इस योजना का उद्देश्य एक लड़की को शादी हो जाने तक **वित्तीय सुरक्षा** प्रदान करना है।
   - **आयु सीमा -** सुकन्या समृद्धि खाता योजना 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए है।
   - खाता **21 वर्ष की आयु** में पूरा (matures) हो जाता है, इससे पहले यह बंद अवधि में रहता है जिसमें धन की निकासी नहीं की जा सकती है।

- इसके अलावा, जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए **ब्याज दर 8.1%** है।
- **लोचदार जमा धनराशि** (Flexible deposit amounts): खाता **250 रुपये की न्यूनतम जमा धनराशि** के साथ खोला जा सकता है और उसके बाद 100 रुपये के गुणकों में धनराशि जमा की जा सकती है।
- प्रत्येक वर्ष प्रति खाता अधिकतम **1.5 लाख रुपये** जमा किए जा सकते हैं।

2. **सरकार ने खेलो-इंडिया छात्रवृत्ति के लिए 734 एथलीटों का चयन किया** - खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई) ने खेलो-इंडिया कौशल विकास योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए 734 एथलीटों को मंजूरी दी है।
   - उन्हें जेब खर्च, चोटों के इलाज और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए तिमाही आधार पर 1,20,000 रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाएगा।

खेलो-इंडिया कौशल विकास योजना

- इस योजना को भारत में आधारभूत स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।
- इसका उद्देश्य हमारे देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए मजबूत रूपरेखा तैयार करना और भारत को महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न खेलों में स्कूलों से युवा प्रतिभा को ढूंढने और उन्हें भविष्य के खेल चैंपियन के रूप में तैयार करने में मदद करना है।

3. **सरकार ने छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम शुरू किया:** गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित छात्र पुलिस कैडेट (एस.पी.सी) कार्यक्रम हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया था।
   - इसे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था।
   - कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में स्कूली कक्षाओं और बाहरी माध्यम से मूल्य और नैतिकता पैदा करके पुलिस और बड़े समुदाय के बीच संपर्क का निर्माण करना है।
4. **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018:** केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एम.डी.डब्ल्यू.एस) ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 (एस.एस.जी 2018) लॉन्च किया है।
   - यह सभी राज्यों और जिलों को गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन के आधार पर स्थान देने के लिए एक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण है।
5. **मध्य प्रदेश सरकार ने सब्सिडीकृत पावर स्कीम 'संबल' लॉन्च की:** मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए 'संबल' नामक एक बकाया बिजली बिल छूट योजना और सब्सिडी वाली बिजली योजना शुरू की है.
   - संबल योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को प्रति माह 200 रुपये की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी.

जून

1. **सौर चरखा मिशन:** राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने सौर चरखा मिशन लॉन्च किया जिसके तहत सरकार हजारों कारीगरों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा।
   - यह विश्व एम.एस.एम.ई. दिवस (27 जून को मनाया गया) के अवसर पर उद्योग संगम (राष्ट्रीय एम.एस.एम.ई. सम्मेलन) की घटना के दौरान शुरू किया गया था।
2. **सूर्यशक्ति किसान योजना**: गुजरात सरकार ने किसानों के लिए सौर ऊर्जा योजना शुरू की- सूर्य शक्ति किसान योजना (एस.के.वाई.) जिससे उन्हें अपने कैप्टिव खपत के लिए बिजली उत्पन्न करने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने और अतिरिक्त बकाया कमाई करने में मदद मिलती है।

3. **सेवा भोज योजना**: संस्कृति मंत्रालय ने लोगों के बीच मुफ्त वितरण के लिए चैरिटेबल धार्मिक संस्थानों (सी.आर.आई.) द्वारा विशिष्ट खाद्य वस्तुओं की खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है.
    - संस्कृति मंत्रालय ने लोगों के बीच मुफ्त वितरण के लिए चैरिटेबल धार्मिक संस्थानों (सी.आर.आई.) द्वारा विशिष्ट खाद्य वस्तुओं की खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना सेवा भोज शुरू की है।
    - इस योजना के तहत, धार्मिक संस्थानों द्वारा खरीदी गई कच्चे खाद्य पदार्थों पर लगाए गए केंद्रीय सामान और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.) के केंद्र का हिस्सा वापस कर दिया जाएगा।
    - यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए लॉन्च की गई है जिसमें कुल व्यय 325.00 करोड़ रूपये है।
4. **स्वाजल योजना**: भारत के 115 आकांक्षा जिलों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए **स्वाजल योजना** शुरू की गई।
    - पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए भारत के 115 आकांक्षा जिलों में स्वाजल योजना शुरू की है।
    - इसमें मौजूदा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) बजट के तहत फ्लेक्सी-फंड के माध्यम से 700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
5. **बिजली बिल माफी योजना:** मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए
    - मध्यप्रदेश सरकार ने मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना 2018 में एक उत्कृष्ट बिजली बिल छूट योजना की घोषणा की।
    - मध्यप्रदेश में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मजदूरों को सब्सिडी दर पर बिजली आपूर्ति मिलेगी।
    - राज्य मंत्रिमंडल ने बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 (सब्सिडी वाली शक्ति प्रदान करने की एक योजना) को भी मंजूरी दी।
6. गोपाबंधु संबादिका स्वास्थ्य बीमा योजना: पत्रकारों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना
    - गोपाबंधु संबादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए पत्रकारों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना है।
    - यह योजना 2 लाख रुपये सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर राज्य के सभी कार्यकारी पत्रकारों को प्रदान करती है।

मई

1. **समग्र शिक्षा योजना:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एच.आर.डी.) ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग शिक्षा योजना शुरू की।

    नोट:
    - मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एच.आर.डी.) ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग शिक्षा योजना शुरू की।
    - इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, सीखने के परिणामों में वृद्धि करना और बच्चों एवं शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
2. जेनरेटर के बिजली भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने **प्राप्ती ऐप** लॉन्च किया है.

    नोट:

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने वेब पोर्टल (www.praapti.in) और ऐप अर्थात् प्राप्ती (जनरेटरों के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए बिजली खरीद में भुगतान मूल्यांकन और विश्लेषण) शुरू किया है।
- वेबपोर्टल और ऐप का उद्देश्य जेनरेटर और डिस्कॉम के बीच बिजली खरीद लेनदेन में पारदर्शिता लाना है।

3. गुजरात सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त उपचार योजना शुरू करें।
    - इस योजना के तहत, राज्य सरकार। पहले 48 घंटों के लिए राज्य में सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित के लिए 50,000 रुपये तक के चिकित्सा खर्चों का भार उठाएगा।
    - नि: शुल्क उपचार में घावों, एक्स-रे, रक्त संक्रमण, आईसीयू और एमआरआई में उपचार, और अस्पताल में उपलब्ध अन्य सभी उपचार शामिल हैं।
4. **राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति** - नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने नई परियोजनाओं के साथ-साथ मौजूदा लोगों के संकरण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति शुरू की।
    - नीति का उद्देश्य ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और भूमि के कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर पीवी हाइब्रिड सिस्टम के प्रचार के लिए एक ढांचा प्रदान करना है।
    - बोली लगाने वालों के साथ व्यवहार्यता और भूमि उपलब्धता के आधार पर इन परियोजनाओं को देश भर में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।
    - एमएनआरई इस नीति के तहत नई संकर परियोजनाओं के लिए एक योजना शुरू करने की प्रक्रिया में भी है।
5. **आईपी नानी** - केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में सम्मेलन में बौद्धिक संपदा (आईपी) शुभंकर आईपी नानी की शुरुआत की।
    - मास्कॉट आईपी नानी एक तकनीक-समझदार दादी है जो अपने पोते "छोटू" उर्फ आदित्य की मदद से आईपी अपराधों का मुकाबला करने में सरकार और प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करती है।
    - आईपी शुभंकर लोगों के बीच बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के महत्व के बारे में जागरूकता फैल जाएगा, खासकर बच्चों को, दिलचस्प तरीके से।
6. **डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना** - मई 2018 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप योजना की वेबसाइट लॉन्च की।
    - इस योजना के तहत, 25 इंटर्न तीन महीने की अवधि के लिए शामिल किए जाएंगे, जिन्हें प्रति माह 10 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
    - यह इंटर्नशिप एक छात्र के लिए योग्य और अनुभवी पर्यवेक्षक और सलाहकार के मार्गदर्शन में पहले हाथ और व्यावहारिक कार्य अनुभव को सुरक्षित करने का अवसर है।
    - यह प्रयोग के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और कक्षाओं में प्राप्त ज्ञान का अभ्यास करने का लक्ष्य रखता है।
7. **रितु बंधु योजना** - तेलंगाना सरकार ने 10 मई, 2018 को करीमनगर जिले के धर्मराजुप-इंदिरानगर गांव में रितु बंधु (किसानों के मित्र) योजना की शुरुआत की।
    - यह योजना एक नई पहल है जो कि किसानों को निवेश सहायता प्रदान करती है, जिनके पास जमीन है।

8. **'SWAYAM'** - मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए ' SWAYAM ' की पहल की है।
    - सरकार विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच का उपयोग करेगी, SWAYAM का उद्देश्य नए और उभरते रुझानों पर ध्यान देने के साथ 1.5 मिलियन उच्च शिक्षा संकाय की शिक्षण तकनीक को अद्यतन करना है।
    - इसे प्राप्त करने के लिए, पहले चरण में, ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए 75 अनुशासन-विशिष्ट राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (एनआरसी) की पहचान की गई है और शिक्षकों को ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से अपने विषयों में नवीनतम विकास के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जाएगा।
    - केन्द्रीय, राज्य और मुक्त विश्वविद्यालयों जैसे कई संस्थान, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण के राष्ट्रीय संस्थान, आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी और अन्य को इस संबंध में एनआरसी के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अप्रैल

1. **अटल न्यू इंडिया चैलेंज** - 26 अप्रैल 2018 को, नीति आयोग ने लोगों के लिए प्रासंगिक नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को लाने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के तहत अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया।

    प्रमुख बिंदु
    - **अनुदान** - अटल इनोवेशन मिशन के तहत आवेदकों को क्षमता, इरादा, और प्रौद्योगिकियों को उत्पादित करने की क्षमता दिखाने वाले 1 करोड़ रुपये तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
    - **उद्देश्य** - इस पहल का उद्देश्य विभिन्न 17 क्षेत्रों में समस्याओं को हल करना है, जो नागरिकों के जीवन में सुधार और रोजगार पैदा करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगा।
    - इस नई पहल के तहत, अटल इनोवेशन मिशन ने सड़क परिवहन और राजमार्गों, आवास और शहरी मामलों, कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता और रेलवे बोर्ड के मंत्रालयों के साथ भागीदारी की है।
2. **उन्नत भारत अभियान** - मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने नई दिल्ली में उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया।
    - इस मिशन का उद्देश्य देश भर के 750 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को पास के गांवों को अपनाना होगा और गांव के लोगों के जीवन से परिचित होने और दिन-प्रतिदिन जीवन में उनके सामने आने वाली समस्याओं से परिचित होने के लिए उनसे मुलाकात करेंगे।
3. **दर्पण-पीएलआई ऐप (DARPAN-PLI App)** - संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में दर्पण-पीएलआई ऐप लॉन्च किया।
    - दर्पण -पीएलआई ऐप भारत में किसी भी डाकघर शाखा में पीएलआई और आरपीएलआई नीतियों के प्रीमियम के संग्रह में मदद करेगा।
    - DARPAN का पूर्ण रूप है - Digital Advancement of Rural Post Office for a New India.
4. **'परियोजना धूप'** - देश में युवाओं के बीच 'विटामिन डी की कमी' के समाधान के लिए **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)** संस्था द्वारा एक पहल 'परियोजना धूप' का शुभारंभ किया गय.

    नोट:
    - विटामिन डी की कमी की बढ़ती घटनाओं को संबोधित करने के लिए, विशेष रूप से युवा लोगों के बीच, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनसीईआरटी, एनडीएमसी और उत्तर एमसीडी

स्कूलों के साथ मिलकर एक अनूठी पहल 'परियोजना ढूप' की शुरुआत की है।

- भारत की खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
- वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा हैं।
- जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश से राज्य सभा का सदस्य हैं।

5. उत्तम (**UTTAM**) ऐप **-** रेल मंत्री और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कोयला गुणवत्ता निगरानी के लिए उत्तम (**UTTAM**) ऐप का शुभारंभ किया।
   - **UTTAM** का मतलब है – Unlocking Transparency by Third Party Assessment of Mined Coal
   - **UTTAM** ऐप कोयला पारिस्थितिक तंत्र में जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रभावशीलता और दक्षता सुनिश्चित करता है।
   - यह नमूनाकरण और कोयला प्रेषण की निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करता है।
6. **स्टडी इन इंडिया** - 18 अप्रैल को, भारत सरकार (भारत सरकार) ने भारत में अध्ययन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपना प्रमुख ' **स्टडी इन इंडिया**' कार्यक्रम शुरू किया है।
   - इसे संयुक्त रूप से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्य पाल सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च किया था।
7. **'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान'** - प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में राम नगर में 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' शुरू किया।
   - इस योजना का उद्देश्य पंचायतों और ग्राम सभाओं की क्षमताओं और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए है।
8. **'अटल अमृत अभियान'** - उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने **असम** राज्य में एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य आश्वासन योजना 'अटल अमृत अभियान' लॉन्च किया

   नोट:
   - यह योजना गरीबी रेखा (बीपीएल) और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी।
   - इस योजना में राज्य की आबादी का 9 2% जिनका वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है शामिल होंगे।
   - असम सरकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।
9. **'रुपश्री योजना'** - **पश्चिम बंगाल** ने राज्य की गरीब लड़कियों के विवाह के लिए 'रुपश्री योजना' शुरू की
   - इस योजना में उस लड़की के परिवार को 25,000 रुपये की एक बार की वित्तीय सहायता का विस्तार करने का प्रस्ताव है, जिसकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये है।
   - पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने इससे पहले महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **'कन्याश्री स्कीम'** नामक एक योजना शुरू की थी।
10. **गंगा हरीतमाला योजना** (गंगा हरियाली योजना) - उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई.

    नोट:
    - इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में हरे रंग की आवरण को बढ़ाने और भूमि के क्षरण को नियंत्रित करना है।

मार्च

1. **'अमा गांव, अमा विकास' कार्यक्रम** - ओडिशा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने और विकास गतिविधियों में खुद को शामिल करने के लिए एक कार्यक्रम "अमा गांव, अमा विकास (हमारे गांव, हमारे विकास)" का शुभारंभ किया है।
2. **"खुशी" योजना** - ओडिशा सरकार ने पूरे राज्य में स्कूल की लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए 'खुशी' योजना की शुरुआत की।
3. **उद्योग सखी पोर्टल** - **माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** ने भारत की महिला उद्यमियों के लिए उद्योग सखी पोर्टल शुरू किया है
4. "सौभाग्य" **योजना** - घरेलू विद्युतीकरण योजना "सौभाग्य" को समर्थन देने के लिए **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** ने बिजली मंत्रालय के साथ से हाथ मिलाया है.
   - केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने घरेलू विद्युतीकरण योजना 'सौभाग्य' के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए छह राज्यों - असम, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में मानव शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ साझेदारी की है।
   - सौभाग्य'(प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना) का उद्देश्य, देश की सभी भागों में समयबद्ध तरीके से सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्रदान करना है।

फरवरी

केंद्रीय बजट 2018 में शुरू की गई योजनाएं

1. कुसुम (**KUSUM**) योजना 2018 - किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2018 में की गई।
   - उद्देश्य: देश भर में सौर खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।
   - बजट आवंटन - 48,000 करोड़ रुपये
   - लाभ - सरकार किसानों को सौर कृषि पंप प्रदान करेगी।
   - लक्ष्य - 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना।
2. आयुष्मान भारत योजना - केंद्रीय बजट 2018 में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के भाग के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र में दो प्रमुख पहलों की घोषणा की गई।

   (i) स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र - इन 1.5 लाख केंद्रों के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को लोगों के घरों के करीब लाया जाएगा। ये केंद्र नि:शुल्क आवश्यक दवाएं और नैदानिक सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे। बजट - बजट ने इस प्रमुख कार्यक्रम के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

   (ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना - राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करेगी। इसमें 50 करोड़ लाभार्थी होंगे। यह योजना दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम होगा।
3. ऑपरेशन ग्रीन - "ऑपरेशन बाढ़" की तर्ज पर केंद्रीय बजट 2018 में एक नईं योजना 'ऑपरेशन ग्रीन' की घोषणा की गई है।
   - उद्देश्य - ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

- यह एक मूल्य निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित कीमत दी गई है।
- इस ऑपरेशन का उद्देश्य किसानों की सहायता करना तथा प्याज, आलू और टमाटर की कीमतों में अनियमित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना और उसे सीमित करने में सहायता करना है।
- बजट आवंटन - 500 करोड़ रुपये।
- उद्देश्य - 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना करना।

4. राष्ट्रीय बांस मिशन (एन.बी.एम) - बांस को 'ग्रीन गोल्ड' करार देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2018 में इस योजना की घोषणा की। यह एक पूर्ण प्रायोजित केंद्रीय योजना है।

- उद्देश्य - देश में बांस क्षेत्र को बढ़ावा देना। इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के लोगों को सहायता मिलेगी।
- बजट आवंटन - 1,290 करोड़ रुपये

5. गोबर धन योजना - गैल्विनाइजिंग जैविक जैव-कृषि संसाधन निधि योजना - केन्द्रीय बजट 2018 में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीणों के लिए नई योजना की घोषणा की है।

उद्देश्य - इसका उद्देश्य गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत ठोस अपशिष्ट और पशु गोबर को जैव-सी.एन.जी और बॉयो-गैस जैसे उपयोगी तत्वों में परिवर्तित किया जाएगा, जिसकी कृषि क्षेत्र में आवश्यकता होती है।

6. किफायती आवास निधि (किफायती आवास योजना) - केंद्रीय बजट 2018 में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कम लागत पर घरों को उपलब्ध कराने की नई योजना की घोषणा की है।

उद्देश्य - कम लागत वाले घरों की मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देना।

प्रमुख बिंदु -

- सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में एक समर्पित किफायती आवास निधि (ए.एच.एफ) की स्थापना करेगी, जो कि भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण देने की कमी और पूरी तरह से सर्विस्ड बॉन्डों से वित्त पोषित होगी।

7. एकलव्य विद्यालय - केंद्रीय बजट 2018 में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आदिवासी समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने की योजना की घोषणा की है।

उद्देश्य - शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख क्रांति लाना।

मुख्य बिंदु -

- इस मिशन के तहत, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति (एस.टी) की आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासियों के प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा।
- "एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समकक्ष होंगे तथा खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।"

8. शिक्षा में अवसंरचना और प्रणालियों का पुनरोद्धार (आर.आई.एस.ई) - भारत को बेहतर शोध प्रदान करना और इसके संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में ऊपर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।

- उद्देश्य - स्वास्थ्य संस्थानों सहित प्रमुख शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देना।
- एजेंसी - उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एच.ई.एफ.ए) को इस पहल के वित्तपोषण हेतु उपयुक्त रूप से संरचित किया जाएगा।

- बजट आवंटन - अगले चार वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये का कुल निवेश।

9. प्रधानमंत्री फैलोशिप योजना- देश में शीर्ष 1,000 बीटैक छात्रों के लिए 'प्रधानमंत्री फैलोशिप योजना' की घोषणा की गई थी, ताकि छात्रों को आई.आई.टी और भारतीय विज्ञान संस्थान (आई.आई.एस.सी) में पी.एच.डी करने का मौका मिल सके।

जनवरी

1. **सरकार ने अटल पेंशन योजना** हेतु नियमों को कम किया है - केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ए.पी.वाई वितरण की पेशकश करने हेतु लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को अनुमति देने के लिए अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई) के नियमों को कम कर दिया है। इस कदम से योजना की कवरेज का विस्तार करने में सहायता की अपेक्षा है।

   ए.पी.वाई की मुख्य विशेषताएं -
   - यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।
   - इसने पहली स्वावलंबन योजना की जगह ली है।
   - आयु सीमा - 18-40 वर्ष
   - पेंशन - इस योजना के तहत, ग्राहक को उनके योगदान के अनुसार, 60 वर्ष की आयु से न्यूनतम गारंटी पेंशन 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रति माह प्राप्त होगी।
   - 60 वर्ष की आयु से पहले योजना में कोई निकास नहीं है।

   नोट: 11.41 लाख ग्राहकों के साथ उत्तर प्रदेश (ए.पी.वाई अकाउंट्स) के बाद बिहार 8.87 लाख ग्राहकों तथा तमिलनाडु 6.60 लाख ग्राहकों के साथ योजना में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य हैं।

2. **महात्मा गांधी सरबत विकास योजना** (एम.जी.एस.वी.वाई) - पंजाब सरकार ने 'महात्मा गांधी सरबत विकास योजना' (एम.जी.एस.वी.वाई) का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य समाज के व्यथित वर्गों का समावेशी विकास करना है।

3. **साइबर सुरक्षित भारत पहल**- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैटी) ने साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत की है।
   - **उद्देश्य -** भारत के विज़न 'डिजिटल इंडिया' की दर्ज पर साइबरसिक्योरिटी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना।

   मुख्य बिंदु -
   - इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (एन.ई.जी.डी) और उद्योग साझेदारों के सहयोग से शुरू किया गया था।
   - साइबर सुरक्षित भारत अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी साझेदारी है।
   - यह साइबरसिक्योरिटी में आई.टी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।
   - इसमें प्रमुख आई.टी कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहैट और डायमेंशन डेटा सहित संस्थापक साझेदार शामिल हैं।

4. **नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना** - महाराष्ट्र राज्य सरकार ने योजना का शुभारंभ किया।
   - उद्देश्य - राज्य में जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा देना।
   - **कुल** बजट -4,000 करोड़ रूपये

   नोट:
   - यह योजना 2018-19 में शुरू हो जाएगी और 2023-24 तक जारी रहेगी।
   - इस योजना का नाम सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने शिक्षा,

स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्म-निर्भरता के क्षेत्र में काम किया है और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।

5. **'स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत'** मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोच्ची, केरला में इस योजना को लांच किया.

• यह कार्यक्रम केन्द्रीय विद्यालय के 12 लाख से अधिक केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों के लिए एक शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रोफाइल कार्ड तैयार करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन की पहल है।

6. **मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना' -** ओडिशा राज्य सरकार ने राज्य में कलाकारों की सहायता हेतु इस योजना को शुरू किया है।

उद्देश्य - राज्य के कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

नोट:

- सरकार ने कलाकार सहायता के रूप में 1200 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया है
- नए पात्रता मानदंडों के अनुसार, पुरुष कलाकार 50 वर्ष की आयु (पहले ये 60 वर्ष थी) के बाद सहायता प्राप्त कर सकता है और महिला कलाकार इसे 40 वर्ष की आयु (पहले ये 50 वर्ष थी) में प्राप्त कर सकती हैं।

7. राष्ट्रीय वायरल हैपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम योजना - इस योजना को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा।

उद्देश्य - इसका ध्यान हेपेटाइटिस C के एंटी-वायरल उपचार पर केन्द्रित होगा, जो सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।

बजट - आगामी तीन वर्षों के लिए 600 करोड़ रुपये।

gradeup

----------xx----------xx----------xx----------xx----

बैंकिंग, एसएससी, गेट, सीटीईटी, जेईई एवं अन्य प्रवेश परीक्षाएं

- नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित
- हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है
- अखिल भारतीय रैंक और परिणाम विश्लेषण प्राप्त करें
- विस्तृत समाधान

ANDROID APP ON Google play